भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी

प्रेस विज्ञप्ति

26 मई, 2015

मोदी के एक साल का कार्यकाल–देश को तेजी से बेचने की कवायद

केंद्र में सत्तारूढ़ हुए मोदी को एक साल पूरा हो गया है। मोदी की ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवादी भाजपा सरकार के एक साल का कार्यकाल देश की सार्वजनिक संपदाओं व संसाधनों को कौडियों के भाव तेजी से बेच डालने, अपनी मातृ संस्था आरएसएस के हिन्दू राष्ट्र के एजेण्डे को आगे बढ़ाने के प्रयासों व विरोध करने वालों पर पाशविक दमन का गवाह रहा। मोदी देश के प्रधान मंत्री की हैसियत से देशी, विदेशी कॉरपोरेट घरानों के प्रधान सेवक की भूमिका बखूबी निभा रहे हैं। मोदी के इस कथन कि वे 'देश' के प्रधान मंत्री नहीं प्रधान सेवक हैं, को इसी मायने में समझना होगा। मोदी वाकई एक साल के भीतर अपनी चहेती 'जनता' – देशी, विदेशी कॉरपोरेट घरानों व सामंती ताकतों के लिए आच्छे दिन लाये हैं। मोदी विकास के गुजरात नमूने को देश भर में लागू कर रहे हैं जिसमें आम आदमी कहीं नजर नहीं आता है। हमारी पार्टी मोदी के एक साल के कार्यकाल को जन विरोधी व देश विरोधी नीतियों जोकि वास्तव में देशी, विदेशी औद्योगिक घरानों की अनुकूल नीतियां ही हैं, को तेजी से अमल करने की कवायद के रूप में देखती है। हमारी पार्टी देश की जनता, जनवादी–प्रगतिशील–देशभक्त ताकतों का आह्वान करती है कि वे मोदी की ब्राह्मणीय हिन्दत्व फासीवादी भाजपा सरकार की जन विरोधी व देश विरोधी नीतियों के खिलाफ व्यापक, संगठित व जुझारु देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन का निर्माण करें ताकि देश की सार्वजनिक संपदाओं, संसाधनों व संप्रभुता को बचाया जा सके।

मोदी के एक साल के शासनकाल पर विहंगम नजर डाले तो यह स्पष्ट होता है कि देश के आम किसान, मजदूर, कर्मचारी, आदिवासी, महिला, दलित व अल्पसंख्यकों के लिए अच्छे दिनों का आना तो दूर की कौडी है, बल्कि बुरे दिन और बढ़ रहे हैं।

काला बाजारी व महंगाई के कम होने का कोई आसार नजर नहीं आ रहा है। पेट्रोल, डीजल के दाम फिर से बढ़ना शुरु हो गया है जोकि आम आदमी के बोझ को लगातार बढ़ायेगा। रेल माल भाड़ा बढ़ाया गया है और प्लेट फॉर्म टिकट का दाम दस रुपए कर दिया गया है जिससे आम आदमी के जीवन पर काफी बुरा असर पडेगा। रेल बजट में यात्री किराया वृद्धि न करके कुछ ही दिन बाद माल भाड़े में बढ़ोत्तरी दरअसल जनता के साथ छल–कपट ही है। हालांकि यह कोई स्थायी समाधान नहीं है, फिर भी महंगाई रोकने के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष के अपने वादे को मोदी सरकार ने अभी तक नहीं निभाया है।

किसानों की आत्महत्याएं लगातार जारी हैं। किसानों को फसल बेचने पर दिया जाने वाला बोनस बंद कर दिया गया है। किसानों के लागत खर्च को कम करने के लिए सब्सिडियां देने का कोई प्रावधान बजट में नजर नहीं आया। खासकर सिंचाई सुविधाओं के लिए कोई विशेष योजना नहीं बनायी गयी। प्रधान मंत्री की महत्वाकांक्षी नदी जोडो योजना दरअसल देश में तबाही का मंजर लेकर आयेगा।

श्रम कानूनों में पूंजीपतिपरस्त बदलावों कों मंजूरी देकर मंत्रिमंडल ने अपने मजदूर विरोधी चरित्र को उजागर किया।

सार्वजनिक संपत्ति व संसाधनों खासकर जल–जंगल–जमीन को देशी, विदेशी पूंजीपतियों के हवाले करने की नीति के तहत ही सर्वव्यापी व तीखे विरोध की परवाह किये बगैर भूमि अधिग्रहण (संशोधन) अध्यादेश को तीसरी बार जबरन अमल में लाया गया है। इस विधेयक को संसद में पारित कराने में नाकाम मोदी सरकार ने तथाकथित संसदीय लोकतंत्र का घोर हनन करते हुए इसे पिछले दरवाजे से लागू किया है।

मोदी 'मेक इन इंडिया' के नाम पर देशी, विदेशी पूंजीपतियों को देश की संपदाओं को लूटने का खुला न्योता दे रहे हैं। साल भर में मोदी ने 19 विदेशी दौरे किये। इन सभी दौरों का वास्तविक मकसद एक ही था। विदेशी कॉरपोरेट घरानों द्वारा भारत में पूंजी निवेश करके सूपर–डूपर मुनाफे कमाने उन्हें मौके उपलब्ध कराना व दुनिया के अन्य पिछडे देशों में देशी दलाल पूंजीपतियों के पूंजी निवेश के समझौते कराना।

मोदी की विदेशी नीति का मुख्य उद्देश्य है, अमेरिका का पिछलग्गु बनकर दक्षिण एशिया में दादागिरी, उसके जरिए अंतर्राष्टीय वित्तीय पूंजी की लूट में दलाल नौकरशाही पूंजीपतियों की दलाली व हिस्सेदारी सुनिश्चित करना।

मोदी ने अपने शासनकाल के पहले बजट में आम आदमी को पूरी तरह भुला दिया था। वह पूरी तरह कॉरपोरेट अनुकूल व जन विरोधी बजट है। सौ स्मार्ट शहरों का निर्माण, बुलेट ट्रेन, सूपर हाइवेज, औद्योगिक गलियारें, एसईजेड, एफडीआई को बेरोकटोक बढ़ावा देना आदि से आम आदमी की तबाही अवश्यंभावी है।

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) एवं अन्य सार्वजनिक उपक्रमों की कुछ प्रतिशत हिस्सेदारी मिट्टी के मोल बेच दी गयी। दूसरी ओर वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश–एफडीआई 11 महीनों में 39 फीसदी बढ़कर 28.81 अरब डॉलर हो गया। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अभूतपूर्व ढ़ंग से एफडीआई सीमा बढ़ा दी गयी। यहां गौर करने वाली बात यह है कि विदेशी पूंजी निवेश को सौ फीसदी करने के सरकार के इरादे पर देश भर का जन विरोध ने पानी फेर दिया था। रेलवे, प्रतिरक्षा, बीमा क्षेत्रों में एफडीआई सीमा बढ़ाकर 49 फीसदी की गयी। मल्टी ब्रांड खुदरा निवेश 51 फीसदी की गयी। देश की आर्थिक, औद्योगिक, खनन, कर आदि तमाम सरकारी नीतियों का एकमात्र मकसद है, आम आदमी की लूट एवं खास को छूट। यह जग जाहिर है कि इन नीतियों से रोजगार के नये अवसरों का खुलना तो दूर की बात लेकिन खुदरा व्यापार एवं अन्य व्यवसायों से जुडे लाखों लोगों की आजीविका छिन गयी।

मोदी के उबाऊ भाषणों, कोरे वादों व भ्रामक प्रचार से देश के 35 साल से कम 65 प्रतिशत युवाओं को अब तक कोई खास रोजगार नहीं मिले हैं।

भ्रष्टाचार पर लगाम कसना हवाई बात रह गयी है। सौ दिन के भीतर विदेशों से कालाधन वापस लाने व इसे जनकल्याण योजनाओं के लिए खर्च करने के मोदी का वादा खोखला साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एसआईटी गठित की गयी लेकिन कोई खास उपलब्धि हासिल नहीं हुई। अब तक सिर्फ 627 विदेशी बैंक खाता धारकों यानी एक प्रतिशत के नाम ही सामने आये हैं। बाकी 99 प्रतिशत के बारे में कोई बात सामने नहीं आयी। हवाला कारोबार यथावत जारी है। पत्रकारों ने भी कई नाम उजागर किये हैं। सरकार ने शर्म–हया छोड़ दी कि वह कालेधन के मामले में कोई भी कार्रवाई करने की कोशिश तक नहीं कर रही है।

2000 करोड के 'नमामि गंगे' अभियान के तहत गंगा की सफाई के लिए एक साल में कोई पैसा खर्च नहीं हुआ है।

मोदी के एक साल के शासनकाल में महिला सुरक्षा का मामला जस का तस है। महिलाओं पर यौन अत्याचारों के मामलों में इजाफा हुआ है। निर्भया निधि से न पिछली सरकार और न ही मोदी सरकार ने पीडितों के लिए कोई खर्च किया है। महिलाओं के लिए विधायिका में 33 प्रतिशत आरक्षण विधेयक को पारित कराने में सरकार नाकाम रही।

आदिवासियों को उपलब्ध संवैधानिक अधिकारों–पांचवी अनुसूची, पेसा कानून से उन्हें वंचित करने मोदी प्रयास कर रहे हैं। आदिवासी बहुल इलाकों में प्रस्तावित बडे बांधों, बडे खदानों, वृहत कारखानों से संबंधित अनगिनत परियोजनाओं की वजह से आदिवासी अपने ही जल–जंगल–जमीन से बेदखल होने के कगार पर हैं और आदिवासी अस्तित्व ही खतरे में पड गया है।

जब से हिन्दुत्व फासीवादी सरकार सत्ता में आयी, तब से वह सांप्रदायिक दंगों के जरिये सामाजिक विभाजन की खुली साजिश कर रही है। धार्मिक अल्प संख्यकों पर हमलें बढ़ गये हैं। गरीब मुसलमानों व ईसाइयों का डरा–धमकाकर, लालच देकर घर वापसी के नाम पर जबरिया धर्मांतरण करवाया जा रहा है।

शोषक सरकारों की जन विरोधी नीतियों व विस्थापन के विरोध में संघर्षरत जनता व नेतृत्व करने वाली हमारी पार्टी को खत्म करने के उद्देश्य से, 2009 से जनता पर जारी पाशविक दमन अभियान ऑपरेशन ग्रीनहंट के तीसरे चरण के तहत हमलें तेज किये गये हैं। बडे पैमाने पर पुलिस, अर्ध सैनिक बलों को तैनात करते हुए नये थानों व कैंप बैठाये जा रहे हैं। पिछले साल भर में गांवों पर हमलें, फर्जी मुठभेडें, अवैध गिरफ्तारियां, लंबी सजाएं बढ़ गयी हैं।

कुलमिलाकर कहा जाए तो मोदी सरकार अपनी पूर्ववर्ती युपीए सरकार की ही एलपीजी (उदारीकरण, निजीकरण एवं भूमंडलीकरण) नीतियों को अभूतपूर्व तेजी से अमल कर रही है जिससे देश पर नव औपनिवेशिक पकड मजबूत हो रही है। देश की संपूर्ण बिक्री, उग्र हिन्दुत्व एजेण्डे को आगे बढाना, बर्बर दमन मोदी के एक साल के शासनकाल की खासियत रही है। हमारी पार्टी एक बार और देश के मजदूरों, किसानों, दलितों, आदिवासियों, अल्प संख्यकों, जनवादी–प्रगतिशील बुद्धिजीवियों का आह्वान करती है कि वे मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करें।

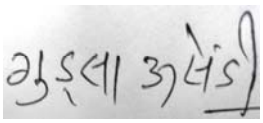

(गुड्सा उसेण्डी)

प्रवक्ता,

दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी,

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)